सं भो वि /रोहतक / 4-85 / 7516. — चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै. मोहन स्पीनिंग मिल, रोहतक, के श्रमिक श्री बाल किशन तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई ग्रौद्योगिक विवाद है;

ग्रीर चूंकि हरियाणा के राज्यवाल विवाद को न्यायिनर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इतिलए, प्रत्न, प्रौद्योगिक विवाद प्रधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रवान की गई गितियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी प्रधिभुचना सं० 9641-1-श्रम/70/3257% दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी प्रधिसूचन। सं० 3864-ए. एस.ग्रो. (ई)श्रम 70/343, दिनांक 8 मई. 1970 द्वारा उक्त प्रधिनियम की धारा 7 के प्रधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादप्रस्त या उससे नुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के दीच या तो विवादप्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत ग्रयवा संबंधित मामला है:---

क्या श्री बाल कि अन की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं श्रो शिव शिहतक | 13-85 | 7523. — चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मैं श्रो गम, एम. ग्राई. ई., बहादुरगढ़ (रोहतक), के श्रीमक श्री नसीरा तथा उसके प्रवन्धकों के इसमें बीच इसके बाद लिखित मामले में कोई मौद्योगिक दिवाद है;

भीर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, धव, प्रौद्योगिक विवाद प्रधिनियम, 1947, की घारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी प्रधिसूचना सं० 9641-1 धम/70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 हे साथ पठित सरकारी अधिस्चना सं. 3864-ए-एस.ब्रो.(ई)श्रम-70/1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त प्रधिनियम की घारा 7 के श्रधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादप्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं, बो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादप्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला है :---

क्या श्री नसीरा की सेवामों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?
सं. म्रो. वि./रोहतक/3-84/7530.—चूं कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि (1) मैनेजिंग डायरेक्टर, हरियाणा स्टेट फैडरेशन म्राफ कन्जूमर को. म्रो. होल-सेल स्टोरज लि., चण्डीगढ़। (2) डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, कानफेड, रोहतक के श्रमिक श्रीमती शिक्षा देवी तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके वाद लिखित मामले में कोई भौद्योगिक विवाद है:

भीर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद ग्रिधिनियम, 1947 की घारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी ग्रिधिसूचना सं. 964:-1श्रम/70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी ग्रिधिसूचना सं. 3864-ए. एस.ग्रो. (ई)श्रम-70/1348 दिनांक 8 मई, 1970, द्वारा उक्त प्रवितिषक को बारा 7 के ग्रिबीन गठित श्रम न्यायालय, रोंहतक, को विवादग्रस्त या उपने प्रवंगन वर उससे सम्बन्धिन नीचे लिखा मामता न्यायिनर्गय के लिये निर्देष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से स्संगत या संबंधित मामला है :---

क्या श्रीमती शिक्षा देवी की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत की हकदार है?

सं. ब्रो. वि./सोनीपत/246-84/7538.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मैं. गोल्डी हार्ड मैक्स पोलटरी फार्म कि., बेगा गन्तीर (सोनीपत) के श्रमिक श्री सत्यपाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई ग्रौद्योगिक विवाद है ;

ग्रौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्याय निर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, भव, भौद्योगिक विनाद ग्रीधिनियम, 1947, की धारा 10 की उप धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई बाक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपान इसके द्वारा सरकारी ग्रीधसूचना सं. 9641-1-श्रम-70/32573, दिनांक ह नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी श्रीधसूचना सं. 7564-ए. एस.ग्रो.(ई)-श्रम/70/1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त ग्रीधिनियम को धारा 7 के प्रधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्याय निर्णय के लिए निद्धिट करते हैं, जो कि उबत श्रवन्धकों सथा श्रीमक के दीच या तो विवादग्रत मामला है था विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला है :---

क्या श्री सत्यपाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठोक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकवार है ?